Vishv UMIYA Foundation | VUF INSTITUTE CIVIL SERVICES

DAILY CURRENT AFFAIRS

IN HINDI

SPECIAL FOR UPSC & GPSC EXAMINATION

DATE : 21-08-25

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Thursday, 21 Aug, 2025

Edition : International Table of Contents

Page 04 **Syllabus : GS 2 : International Relation**	रूस ने वांग यी की यात्रा और भारत-चीन संबंधों में सकारात्मक बदलाव का स्वागत किया
Page 04 **Syllabus : GS 2 : International Relation**	मास्को में, जयशंकर ने भारत-रूस व्यापार के लिए टैरिफ से उत्पन्न चुनौतियों की ओर इशारा किया
Page 05 **Syllabus : GS 3 : Science and Technology**	भारत ने अग्नि-5 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया
Page 08 **Syllabus : GS 2 : Social Justice**	दंड प्रक्रिया: लिंग पहचान को नौकरशाही की बाधाओं में नहीं फँसाया जाना चाहिए
Page 10 **Syllabus : GS 3 : Science and Technology**	भारत को राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की आवश्यकता क्यों है
Page 08 : Editorial Analysis **Syllabus : GS 3 : Indian Economy**	भारत का लोकतंत्र प्रवासी नागरिकों को निराश कर रहा है

Page 04 : GS 2 : International Relation

हाल ही में रूस ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा का स्वागत किया है और भारत-चीन संबंधों में आ रहे सकारात्मक बदलाव को सराहा है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब वैश्विक राजनीति में अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों, व्यापार युद्ध और महाशक्तियों के बीच नए गठजोड़ों के चलते तनाव बढ़ रहा है। रूस का यह रुख न केवल ब्रिक्स (BRICS) और शंघाई सहयोग संगठन (SCO) जैसे बहुपक्षीय मंचों की महत्ता को रेखांकित करता है, बल्कि भारत-रूस ऊर्जा और रक्षा सहयोग की मजबूती को भी सामने लाता है।

Russia welcomes Wang Yi's visit and the positive turn in India-China ties

Kallol Bhattacherjee
NEW DELHI

Russia has welcomed Chinese Foreign Minister Wang Yi's visit to India and the positive turn in India-China relations.

Addressing a press meeting at the Russian Embassy on Wednesday, senior Russian diplomats further said that India-Russia energy trade has not been impacted by U.S. President Trump's penalty tariffs targeting India, and that Russia currently supplied more than 40% of India's total crude oil.

They also said that Russia would step up cooperation in India's defence sector and participate in the development of jet engines and the multi-layered air-defence system - Sudarshan Chakra.

"We welcome the very successful visit by Chinese Foreign Minister Wang Yi," said Roman Babushkin, *Chargé d'affaires* at the Russian Embassy, highlighting the need for stronger ties among members of the BRICS and the Shanghai Cooperation Organisation (SCO).

> You will never see sanctions imposed by Russia or within BRICS organisations where we collectively participate. Non-UN sanctions and secondary sanctions are illegal
>
> **ROMAN BABUSHKIN**
> Chargé d'affaires at the Russian Embassy in India

The senior Russian official, accompanied by Russia's Deputy Trade Commissioner in India, Evgeny Griva, said that BRICS member countries can come up with a collective response to the tariffs imposed by Mr. Trump.

'Unlawful tools'

He further called the additional tariff imposed on India as "illegal" and "unlawful" tools that "disrespected national interests".

He highlighted the need for closer cooperation among countries in the Global South to deal with global challenges.

However, Mr. Babushkin declined to give a timeline for a Russia-India-China summit, saying that such a meeting would take place at the "right time", though he said the leaders of the three nations would meet in Tianjin, where the Heads of State Council meeting of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) would take place during August 31 and September 1.

"You will never see sanctions imposed by Russia or within BRICS organisations where we collectively participate. Non-UN sanctions and secondary sanctions are illegal. They only serve to weaponise the economy," said Mr. Babushkin.

He described the energy ties between India and Russia as having remained unaffected by tariffs and sanctions from the U.S. and the EU, as India-Russia energy trade uses a "very special mechanism" to bypass Western sanctions.

The senior official said, "Russia is a partner of choice for India's defence sector", and that it has been working on the Make in India vision since the 1980s.

He said that Russia would participate in future jet engine projects as well as in building the Sudarshan Chakra, the multi-layered missile defence system that was announced by Prime Minister Narendra Modi in his Independence Day speech.

Mr. Babushkin highlighted the S400 air defence system and said these systems underwent a "very successful battle test" during Operation Sindoor when India fought a brief war with Pakistan in May.

प्रमुख विश्लेषण बिंदु

1. रणनीतिक संदेश

- रूस ने वांग यी की यात्रा का स्वागत करके यह संदेश दिया कि वह भारत-चीन संबंधों की स्थिरता का समर्थन करता है, भले ही 2020 के गलवान संघर्ष के बाद से दोनों देशों के बीच अविश्वास बना हुआ है।
- रूस मानता है कि RIC (Russia-India-China) सहयोग बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को मजबूत करने और पश्चिमी प्रभुत्व का संतुलन बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।

2. ऊर्जा संबंध – प्रतिबंधों के बीच मजबूती

- रूस भारत को उसकी कुल कच्चे तेल की आवश्यकताओं का 40% से अधिक आपूर्ति कर रहा है।
- अमेरिका की "पेनल्टी टैरिफ" और यूरोपीय प्रतिबंधों के बावजूद, विशेष व्यापार तंत्रों के माध्यम से भारत-रूस ऊर्जा व्यापार प्रभावित नहीं हुआ है।
- यह दर्शाता है कि दोनों देश पश्चिम-नियंत्रित वित्तीय प्रणालियों से स्वतंत्र विकल्प तैयार कर रहे हैं।

3. रक्षा सहयोग और भविष्य की परियोजनाएँ

- रूस ने भारत के लिए खुद को "पसंदीदा रक्षा साझेदार" बताया और कहा कि वह 1980 के दशक से 'मेक इन इंडिया' में सहयोग करता रहा है।
- नए क्षेत्रों में जेट इंजन विकास और 'सुदर्शन चक्र' बहु-स्तरीय रक्षा प्रणाली का निर्माण शामिल है।
- रूस ने यह भी रेखांकित किया कि S-400 रक्षा प्रणाली का सफल उपयोग "ऑपरेशन सिंदूर" (भारत-पाकिस्तान संघर्ष) में हुआ।

4. अमेरिकी प्रतिबंधों की आलोचना

- रूस ने अमेरिकी प्रतिबंधों को "गैर-कानूनी" और "अवैध औज़ार" बताया, जो राष्ट्रीय हितों का उल्लंघन करते हैं।
- यह भारत की उस चिंता से मेल खाता है, जिसमें वह एकतरफा प्रतिबंधों को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के लिए चुनौती मानता है।

5. वैश्विक दक्षिण और बहुपक्षीय सहयोग

- रूस ने वैश्विक दक्षिण (Global South) के देशों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया।
- BRICS और SCO जैसे मंचों को पश्चिमी दबाव का सामूहिक रूप से जवाब देने का माध्यम बताया गया।

चुनौतियाँ और चिंताएँ

- रूस की सकारात्मकता के बावजूद भारत-चीन संबंधों में गहरा अविश्वास है। सीमा विवाद और सुरक्षा चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
- भारत को रूस और चीन से संबंध बनाए रखने के साथ-साथ अमेरिका और क्वाड देशों के साथ भी अपनी साझेदारी को संतुलित करना होगा।

- रक्षा क्षेत्र में अत्यधिक रूसी निर्भरता भविष्य में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को सीमित कर सकती है।

निष्कर्ष

रूस द्वारा वांग यी की भारत यात्रा का स्वागत और रक्षा व ऊर्जा सहयोग को आगे बढ़ाने का वादा यह दर्शाता है कि वह बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में भारत को अपने करीब बनाए रखना चाहता है। भारत के लिए चुनौती यह है कि वह इन संबंधों का लाभ उठाते हुए अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखे और अमेरिका व पश्चिमी देशों के साथ बढ़ती साझेदारी को संतुलित करे। भविष्य में भारत-रूस-चीन त्रिपक्षीय सहयोग इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत सीमा विवादों और रणनीतिक निर्भरता जैसी जटिलताओं को किस तरह सुलझाता है।

UPSC Mains Practice Question

Ques: भारत-चीन संबंधों में सुधार के प्रति रूस का समर्थन तथा भारत के साथ उसके ऊर्जा एवं रक्षा सहयोग पर बल देना, भारत की विदेश नीति के लिए अवसरों और चुनौतियों दोनों को रेखांकित करता है। विवेचना कीजिए। **(150 Words)**

Page 04 : GS 2 : International Relation

विदेश मंत्री एस. जयशंकर की मॉस्को यात्रा (26वां भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग : IRIGC-TEC) ने द्विपक्षीय व्यापार के अवसरों और चुनौतियों को रेखांकित किया। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए दंडात्मक टैरिफ तथा वैश्विक व्यापार व्यवधानों की पृष्ठभूमि में, इस बैठक में भारत-यूरेशियन आर्थिक संघ (EAEU) के साथ मुक्त व्यापार समझौता (FTA), बेहतर कनेक्टिविटी और भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया गया। यह यात्रा इस बात का संकेत है कि भारत, पश्चिमी प्रतिबंधों से परे रहते हुए रूस के साथ अपने आर्थिक रिश्तों को मज़बूत करना चाहता है।

In Moscow, Jaishankar flags challenges that tariffs pose to India-Russia trade

Kallol Bhattacherjee
NEW DELHI

Timely ties: S. Jaishankar with Denis Manturov during a meeting in Moscow on Wednesday. PTI

In the backdrop of U.S. President Donald Trump's imposition of penalty tariffs on India, External Affairs Minister S. Jaishankar on Wednesday in Moscow raised the challenge posed by "tariff and non-tariff trade barriers" against Russia-India trade and called for the "early conclusion" of a Free Trade Agreement between India and the countries of the Eurasian region.

Mr. Jaishankar made the remarks during the 26th Session of the India-Russia Inter-Government Commission for Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation (IRIGC-TEC) where the Russian side was being led by First Deputy Prime Minister of Russia Denis Manturov.

Delivering his opening remarks, Mr. Jaishankar said some of the main issues before the IRIGC-TEC were "tariff and non-tariff trade barriers, removing bottlenecks in logistics, promoting connectivity, and effecting payment mechanisms smoothly".

Free trade pact

He said Wednesday's meeting in Moscow also finalised the terms of reference of the India-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement of which Russia has been a leading proponent as it aims at removing obstacles for overland trade among Russia, China, India and the Central Asian countries.

"...We are all acutely aware that we are meeting in the backdrop of a complex geopolitical situation. Our leaders remain closely and regularly engaged," Mr. Jaishankar said indirectly referring to the trade-related anxieties in India-U.S. relations.

India's trade with Russia grew from $13 billion in 2021 to $68 billion in 2024-25. The bulk of this trade is in hydrocarbon that Russia supplies to India.

मुख्य बिंदु

1. **टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाएँ**
    - जयशंकर ने "टैरिफ और गैर-टैरिफ अवरोधों" को भारत-रूस व्यापार के प्रमुख अवरोधक बताया।
    - लॉजिस्टिक्स, कनेक्टिविटी और भुगतान व्यवस्था पर पश्चिमी वित्तीय प्रतिबंधों का दबाव स्पष्ट है।
2. **भारत-यूरेशियन आर्थिक संघ (EAEU) FTA**
    - बैठक में EAEU (रूस, बेलारूस, आर्मेनिया, कज़ाख़स्तान, किर्गिज़स्तान) के साथ FTA की रूपरेखा तय हुई।
    - यह समझौता व्यापारिक प्रतिबंध कम करेगा, स्थल मार्ग से व्यापार को बढ़ावा देगा और भारत को मध्य एशिया की अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ेगा।
3. **भू-राजनीतिक संदर्भ**
    - बातचीत ऐसे समय हुई जब भारत-अमेरिका व्यापार संबंध टैरिफ विवाद से प्रभावित हैं।
    - जयशंकर ने "जटिल भू-राजनीतिक परिस्थिति" का उल्लेख करते हुए भारत की संतुलनकारी कूटनीति को रेखांकित किया।
4. **व्यापार वृद्धि और ऊर्जा प्रधानता**
    - भारत-रूस व्यापार 2021 में 13 अरब डॉलर से बढ़कर 2024-25 में 68 अरब डॉलर पहुँच गया।
    - इसका बड़ा हिस्सा रूस से आयातित कच्चे तेल पर आधारित है।
    - अन्य क्षेत्रों (आईटी, फार्मा, कृषि) में विविधीकरण अभी सीमित है।
5. **भारत के लिए सामरिक महत्व**
    - रूस और EAEU के साथ व्यापारिक साझेदारी भारत को पश्चिम-प्रधान बाजारों और वित्तीय प्रणालियों का विकल्प देती है।
    - यह भारत की बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की दृष्टि और मध्य एशिया से संपर्क बढ़ाने की रणनीति से मेल खाती है।
    - किंतु, रूस के साथ गहरे संबंध बनाए रखना अमेरिका और क्वाड देशों के साथ सामरिक तालमेल को जटिल बना सकता है।

चुनौतियाँ

- असंतुलित व्यापार टोकरी: तेल पर अत्यधिक निर्भरता।
- भुगतान और लॉजिस्टिक्स की कठिनाई: पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण बैंकिंग व बीमा तंत्र प्रभावित।
- भू-राजनीतिक संतुलन: रूस के साथ घनिष्ठता से भारत की पश्चिमी साझेदारियों में गलत संदेश का खतरा।
- FTA क्रियान्वयन: विभिन्न देशों की विविध प्राथमिकताओं के कारण वार्ता कठिन।

निष्कर्ष

जयशंकर की मॉस्को यात्रा भारत की व्यावहारिक कूटनीति को दर्शाती है, जिसमें वह व्यापार विविधीकरण और पश्चिमी टैरिफ/प्रतिबंधों के असर को कम करने की कोशिश कर रहा है। भारत-EAEU FTA एक रणनीतिक कदम है जो भारत को यूरेशिया से गहराई से जोड़ सकता है। किंतु, रूस के साथ साझेदारी बढ़ाते हुए अमेरिका और पश्चिमी देशों से संबंध संतुलित रखना भारत की सबसे बड़ी चुनौती बनी रहेगी।

UPSC Mains Practice Question

Ques: हाल के वर्षों में भारत-रूस व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, किंतु टैरिफ अवरोधों, भुगतान प्रणाली और हाइड्रोकार्बन पर अत्यधिक निर्भरता जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। प्रस्तावित भारत–यूरेशियन आर्थिक संघ (EAEU) मुक्त व्यापार समझौते का सामरिक महत्व स्पष्ट कीजिए। **(150 Words)**

Page : 05 : GS 3 : Science and Technology

ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से भारत ने अग्नि-5 मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल (IRBM) का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड (SFC) के तहत हुआ और सभी तकनीकी व परिचालन मानकों को मान्य किया। लगभग 5,000 किमी की मारक क्षमता वाली यह मिसाइल भारत की रणनीतिक प्रतिरोध क्षमता को मज़बूती प्रदान करती है।

India successfully test-fires Agni-5 intermediate-range ballistic missile

The Hindu Bureau
NEW DELHI

India on Wednesday successfully test-fired its intermediate-range ballistic missile Agni-5 from the Integrated Test Range at Chandipur, Odisha.

In a statement, the Defence Ministry said the launch validated all operational and technical parameters and was conducted under the aegis of the Strategic Forces Command. "The intermediate-range ballistic missile Agni-5 was successfully test-fired from Chandipur on August 20. The launch validated all operational and technical parameters," the Ministry said.

The missile tested on Wednesday was a variant of Agni-5, India's intercontinental ballistic missile (ICBM) with a range of 5,000 km. Designed by the Defence Research and Development Organisation (DRDO), the system has been developed keeping in view the country's security requirements.

Previous trial

The previous trial of Agni-5 was conducted on March 11, 2024, when the DRDO successfully tested the missile equipped with Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle technology, allowing it to strike multiple targets with a single launch.

The intermediate-range Agni-5 missile was test-fired from the Integrated Test Range at Chandipur in Odisha. FILE PHOTO

प्रमुख विश्लेषण बिंदु

1. **रणनीतिक महत्व**
   - अग्नि-5 की रेंज सम्पूर्ण एशिया (विशेषकर चीन) और यूरोप के कुछ हिस्सों तक है।
   - यह भारत की न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिरोध (Credible Minimum Deterrence) नीति को सुदृढ़ करता है।

2. **प्रौद्योगिकीय उन्नति**
   - इस परीक्षण ने उन्नत तकनीकी एवं परिचालन मानकों को मान्यता दी।
   - पूर्व परीक्षण में MIRV (Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle) तकनीक शामिल थी, जिससे एक मिसाइल एक साथ कई लक्ष्यों को भेद सकती है।
3. **भूराजनीतिक संदर्भ**
   - चीन की बढ़ती आक्रामकता और चीन-पाकिस्तान गठजोड़ के बीच यह परीक्षण भारत की निवारक क्षमता (Deterrence) को सशक्त बनाता है।
   - यह भारत की इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सामरिक स्थिति को संतुलित करता है।
4. **स्वदेशी क्षमता और रक्षा तैयारी**
   - अग्नि-5 का निर्माण डीआरडीओ (DRDO) ने किया है, जो भारत की आत्मनिर्भरता और 'आत्मनिर्भर भारत' पहल को मज़बूती देता है।
   - यह मिसाइल भारत की स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड को और अधिक सक्षम बनाती है।
5. **अंतरराष्ट्रीय निहितार्थ**
   - भारत की परमाणु नीति रक्षात्मक है और नो-फ़र्स्ट यूज़ (NFU) पर आधारित है।
   - मिसाइल परीक्षण से पड़ोसी देशों, खासकर चीन में चिंता हो सकती है, पर भारत वैश्विक अप्रसार मानदंडों का पालन करता है।

चुनौतियाँ

- क्षेत्रीय हथियार प्रतिस्पर्धा की संभावना (चीन-पाकिस्तान)।
- रक्षा बजट पर भारी लागत का दबाव।
- उन्नत मिसाइल-रोधी प्रणालियों का समुचित विकास आवश्यक।

निष्कर्ष

अग्नि-5 का सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक प्रतिरोध क्षमता, स्वदेशी तकनीकी प्रगति और परमाणु निवारक शक्ति को नई ऊँचाई देता है। यह भारत को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में और अधिक मज़बूत बनाता है। भविष्य की चुनौती यह होगी कि भारत सुरक्षा आवश्यकताओं और कूटनीतिक संतुलन – दोनों को साधते हुए क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखे।

UPSC Prelims Practice Question

Ques: अग्नि–5 मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसकी मारक क्षमता लगभग 5,000 किमी है, जो इसे मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल (IRBM) श्रेणी में रखती है।
2. इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है और यह स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड द्वारा संचालित होती है।
3. इसके नवीनतम संस्करण में MIRV (Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle) तकनीक मौजूद है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

Ans : d)

UPSC Mains Practice Question

Ques : अग्नि–5 जैसी स्वदेशी तकनीकी प्रगतियाँ भारत की रक्षा तैयारी तथा आत्मनिर्भर भारत दृष्टि को किस प्रकार सशक्त बनाती हैं, स्पष्ट कीजिए। **(150 Words)**

Page 08 : GS 2 : Social Justice

मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा डॉ. बियोंसी लैश्रम, एक ट्रांसजेंडर महिला, को नए शैक्षणिक प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश केवल व्यक्तिगत न्याय ही नहीं, बल्कि व्यापक स्तर पर ट्रांसजेंडर अधिकारों की स्थिति को भी उजागर करता है। नालसा बनाम भारत संघ (2014) और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का (अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 में आत्म-पहचान के अधिकार को मान्यता दी गई है, परंतु व्यवहार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आज भी नौकरशाही कठोरता से जूझना पड़ता है।

मुख्य विश्लेषण

1. **कानूनी ढाँचा और अधिकार**
    - नालसा निर्णय (2014): आत्म-पहचान के अधिकार को मान्यता तथा कल्याणकारी उपायों का निर्देश।
    - ट्रांसजेंडर अधिनियम, 2019: आधिकारिक दस्तावेजों में स्व-घोषित लिंग की स्वीकृति।
    - संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 14 (समानता) और 21 (गरिमा सहित जीवन का अधिकार)।
2. **जमीनी हकीकत : नौकरशाही अड़चनें**
    - विश्वविद्यालयों व बोर्डों द्वारा जन्म प्रमाणपत्र से शुरू होकर क्रमवार संशोधन की अनिवार्यता।
    - प्रक्रिया पर जोर, कानून की भावना की उपेक्षा।
    - आधिकारिक अभिलेखों और वास्तविक लैंगिक पहचान के बीच असंगति से शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सेवाओं में बहिष्करण।
3. **ट्रांसजेंडर समुदाय पर प्रभाव**
    - साधारण अधिकार पाने हेतु महँगी और लंबी कानूनी लड़ाइयाँ।
    - औपचारिक मान्यता के बावजूद हाशियाकरण।
    - प्रशासनिक तंत्र में संवेदनशीलता और प्रशिक्षण का अभाव।
4. **निर्णय का महत्व**
    - प्रक्रियात्मक कठोरता पर संवैधानिक गारंटी की प्रधानता।
    - भविष्य में अन्य मामलों के लिए न्यायिक नज़ीर।
    - प्रशासनिक सुधार की दिशा में स्पष्ट संदेश।

Punishing process

Gender identity recognition must not be trapped in bureaucratic hurdles

The Manipur High Court's order to the State to issue fresh academic certificates to Beoncy Laishram is at once a matter of individual justice and a larger commentary on the state of transgender rights. What should have been a simple administrative correction became a legal battle, not because the law lacks provisions but because its implementation remains frustrated by inertia and bureaucratic rigidity. In *NALSA vs Union of India*, the Supreme Court recognised the right to self-identify gender and ordered the state to treat transpersons as socially and educationally backward classes entitled to welfare measures. The principle was codified in the Transgender Persons (Protection of Rights) Act 2019, which also obligated authorities to recognise a person's self-identified gender and issue official documents. Together with Articles 14 and 21 of the Constitution, transpersons are thus entitled to having their affirmed identity seamlessly recognised in all institutional records. Yet, their lived reality is very different. Despite the law being clear on self-identification, bureaucratic setups often do not act unless compelled by higher authorities. In Dr. Laishram's case, her university refused to update her educational records citing procedural hurdles – symptomatic of a systemic malaise. Administrators routinely defer to the most restrictive reading of procedure rather than the spirit of the law. In the present matter, the university and education boards insisted that corrections must begin with the earliest certificate, qualifying recognition on a cascading set of bureaucratic approvals.

Where the law envisages gender as a matter of self-determination for transgender individuals, many officials remain wedded to the binary markers assigned at birth, and the mismatch translates into a stunted application of a simple idea. The insistence on sequential corrections or elaborate justifications is essentially a refusal to accept that gender identity is not derived from paperwork. Dr. Laishram's struggle also shows how institutional reluctance to operationalise this principle forces transpersons into prolonged legal contests over what should be routine matters. Such episodes reveal a troubling truth: transpersons, navigating stigma and discrimination, are forced to expend disproportionate time and resources to access rights that are legally theirs. The High Court judgment is undoubtedly positive: it also sets a precedent that may help other transpersons and signals to administrators that procedural rigidity cannot override constitutional and statutory guarantees. Bridging the gap between legal rights and their application will require both institutional reform and cultural change within the bureaucracy that draw from an understanding of gender as lived reality.

आगे की राह

- प्रशासनिक सुधार: सरल प्रक्रियाएँ, आत्म-घोषणा को पर्याप्त आधार।
- जागरूकता व प्रशिक्षण: अधिकारियों को लिंग को जीवित अनुभव के रूप में समझाना।
- तकनीकी उपाय: एकीकृत डिजिटल प्रणाली द्वारा सभी अभिलेखों में एक साथ परिवर्तन।
- सांस्कृतिक बदलाव: समावेशन और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

मणिपुर उच्च न्यायालय का निर्णय लैंगिक न्याय की दिशा में सकारात्मक कदम है, लेकिन यह कानून और क्रियान्वयन के बीच गहरी खाई को भी दिखाता है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को उनके संवैधानिक व वैधानिक अधिकारों का पूर्ण लाभ तभी मिलेगा जब भारत नौकरशाही कठोरता से आगे बढ़कर गरिमा, समानता और सहानुभूति आधारित शासन संस्कृति को अपनाएगा।

UPSC Mains Practice Question

Ques: प्रगतिशील न्यायिक निर्णयों और विधायी उपायों के बावजूद भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपने बुनियादी अधिकारों तक पहुँचने में नौकरशाही अड़चनों का सामना करना पड़ता है। हाल की घटनाओं के संदर्भ में चर्चा कीजिए। **(150 Words)**

Page 10 : GS 3 : Science and Technology

भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम हाल के वर्षों में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल कर चुका है — चंद्रयान-3 की सफलता से लेकर आगामी गगनयान मिशन और भारत अंतरिक्ष स्टेशन की योजना तक। लेकिन तकनीकी प्रगति के बावजूद भारत के पास अभी भी कोई व्यापक राष्ट्रीय अंतरिक्ष क़ानून नहीं है। निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को देखते हुए, एक स्पष्ट क़ानूनी ढाँचा आवश्यक है ताकि सुरक्षा, जवाबदेही और वैश्विक विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके।

Why India needs a national space law

What does the Outer Space Treaty of 1967 stipulate? Is it self-executing? Why is it important that countries enact their own national space legislations? What has been India's approach to space legislation? Why is creating affordable insurance frameworks for space startups crucial?

EXPLAINER

Shrawani Shagun

The story so far:

India is set to celebrate its second National Space Day on August 23. Following Chandrayaan-3's soft-landing near the lunar south pole to the upcoming Gaganyaan and Chandrayaan missions, as well as the Bharat Antariksh Station, the Indian space programme is set to make history many times over. Yet an essential component remains grounded – the legal architecture. In the race to explore, innovate, and commercialise outer space, a strong space law is necessary.

What about global space legislation?

The Outer Space Treaty of 1967 establishes that space is the province of all mankind, and therefore prohibits national appropriation, and places responsibility on states for national activities in space, whether conducted by the government or private entities. Its companion agreements create binding frameworks of rights, responsibilities, and liability rules. However, these treaties are not self-executing. According to Aarti Holla-Maini, director of the United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA), "The core United Nations treaties on outer space provide the foundational principles for all space activities: from the peaceful use of outer space to the responsibility and liability of states. National legislation is the means by which nations can give effect to these principles domestically, ensuring that their growing space sectors develop in a safe, sustainable, and internationally responsible way." India has ratified the key UN space treaties but it is still in the process of enacting comprehensive national space legislation.

While space policy may signal intent, law is what creates an enforceable structure. "National space legislation offers predictability, legal clarity, and a stable regulatory environment for both government and private actors," Rossana Deim-Hoffmann, UNOOSA Global Space Law Project Lead said. Many countries now have national space legislation. Japan, Luxembourg, and the U.S. have enacted frameworks to facilitate licensing, liability coverage, and commercial rights over space activities.

The ISRO carrying out the Well Deck trials of the Gaganyaan missions's crew module in 2024. FILE PHOTO

Will India enact similar legislation?

India's approach to space legislation reflects a methodical, incremental strategy. As space law expert Ranjana Kaul notes, "It should be understood that national space legislation includes two cardinal interdependent aspects: (i) technical regulations governing space operations in orbit by commercial entities – this is the first aspect of 'authorisation' process under Article VI [of the Outer Space Treaty]. The Department of Space is proceeding meticulously in this matter."

This methodical approach has yielded concrete regulatory developments, which includes the Catalogue of Indian Standards for Space Industry, critical for ensuring the safety of space operations; the Indian Space Policy, providing details of activities that non-governmental entities are encouraged to undertake; and the IN-SPACe Norms, Guidelines and Procedures (NPG) for implementation of Indian Space Policy, 2023, in respect of authorisation of space activities.

However, the second component is still pending. According to Dr. Kaul, "(ii) the overarching regulatory framework (textual part) – this is the ... 'space activities law' that will contain provisions of the OST that are meticulously, carefully, appropriately drafted."

What are industry perspectives?

From the industry's standpoint, the current regulatory transition creates significant operational challenges. Gp. Capt. T.H. Anand Rao (retd.), director of the Indian Space Association, identified priorities for national space legislation beginning with the fundamental need for a statutory authority.

"IN-SPACe, which currently operates without formal legal backing, requires clear statutory authority to strengthen its role as the central regulatory body," Mr. Rao said. "The national space law should clearly set out licensing rules, qualifications, application processes, timelines, fees, and reasons for acceptance or denial, to avoid unnecessary delays and confusion from multiple ministry approvals." The dual-use nature of space technologies creates particular complications, with companies facing delays from multiple ministry clearances even after provisional approvals. Clear FDI rules, such as allowing 100% FDI in satellite component manufacturing under automatic routes, would attract critical capital for startups to scale operations. This operational clarity extends to liability frameworks, with Mr. Rao emphasising that "while India is ultimately responsible internationally, private companies must hold proper third-party insurance to cover any damages. This includes creating affordable insurance frameworks for startups managing high-value space assets. Innovation protection remains equally crucial, "legislation should secure intellectual property rights without excessive government control, encourage partnerships among industry, academia, and government, and foster investor trust." This balanced approach would prevent migration of talent and technologies to more IP-friendly jurisdictions. Mr. Rao also stressed the need for mandatory accident investigation procedures, enforceable space debris management laws, unified frameworks for space-related data and satellite communications, and an independent appellate body to prevent conflicts of interest. Without statutory backing, IN-SPACe's decisions remain vulnerable to procedural challenges.

Shrawani Shagun is a researcher focusing on environmental sustainability and space governance.

THE GIST

- The Outer Space Treaty of 1967 establishes that space is the province of all mankind, and therefore prohibits national appropriation, and places responsibility on states for national activities in space, whether conducted by government or private entities.
- India's approach to space legislation reflects a methodical, incremental strategy.
- Gp. Capt. T.H. Anand Rao (retd.), director of the Indian Space Association, identified priorities for national space legislation beginning with the fundamental need for a statutory authority.

वैश्विक परिप्रेक्ष्य : बाह्य अंतरिक्ष संधि (1967)

- अंतरिक्ष को संपूर्ण मानवता की धरोहर घोषित किया गया है, राष्ट्रीय स्वामित्व पर रोक।
- सभी गतिविधियों के लिए राज्य जिम्मेदार, चाहे वे सरकारी हों या निजी।
- अंतरिक्ष में होने वाले नुकसान के लिए दायित्व सिद्धांत।
- यह संधि स्वतः लागू नहीं होती → देशों को इसे लागू करने के लिए राष्ट्रीय कानून बनाने पड़ते हैं।

अमेरिका, जापान, लक्ज़मबर्ग जैसे देशों ने पहले ही अपने-अपने राष्ट्रीय अंतरिक्ष क़ानून बना लिए हैं।

भारत की अब तक की पहल

- भारत ने प्रमुख संयुक्त राष्ट्र अंतरिक्ष संधियों का अनुमोदन किया है।
- भारतीय अंतरिक्ष नीति, 2023,
- IN-SPACe दिशानिर्देश एवं प्रक्रियाएँ,
- और Catalogue of Indian Standards जैसी पहलें की गई हैं।
- किंतु अभी तक व्यापक Space Activities Law (अंतरिक्ष गतिविधि क़ानून) अधिनियमित नहीं हुआ है।

भारत को राष्ट्रीय अंतरिक्ष क़ानून की आवश्यकता क्यों है?

1. **निजी क्षेत्र के लिए क़ानूनी स्पष्टता**
    - IN-SPACe को विधिक अधिकार नहीं है।
    - लाइसेंसिंग नियम, समय-सीमा, शुल्क, और FDI मानदंड क़ानून में तय होने चाहिए।
2. **दायित्व और बीमा ढाँचा**
    - बाह्य अंतरिक्ष संधि के तहत किसी भी नुकसान के लिए भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्तरदायी है।
    - निजी कंपनियों के लिए सस्ती बीमा व्यवस्था आवश्यक है।
3. **निवेश और नवाचार को प्रोत्साहन**
    - स्पष्ट बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) और निवेशक-अनुकूल नियम निजी निवेश को आकर्षित करेंगे।
4. **सुरक्षा और सततता**
    - दुर्घटना जाँच प्रक्रिया,
    - अंतरिक्ष मलबा प्रबंधन कानून,
    - उपग्रह संचार एवं डेटा प्रबंधन के लिए एकीकृत ढाँचा।

5. **संस्थागत सशक्तिकरण**
    - IN-SPACe को वैधानिक अधिकार देना।
    - विवाद समाधान के लिए स्वतंत्र अपीलीय निकाय की स्थापना।

आगे की राह

- एक व्यापक राष्ट्रीय अंतरिक्ष क़ानून बनाना आवश्यक है।
- यह क़ानून अंतरराष्ट्रीय दायित्वों और भारत की रणनीतिक प्राथमिकताओं दोनों को संतुलित करे।
- इसमें सस्ती बीमा, IPR सुरक्षा, और FDI प्रोत्साहन जैसे प्रावधान शामिल हों।
- सतत अंतरिक्ष उपयोग सुनिश्चित करने के लिए मलबा प्रबंधन और पर्यावरणीय मानक अपनाना ज़रूरी है।

निष्कर्ष

भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम अब सरकार-प्रमुख मॉडल से सार्वजनिक-निजी साझेदारी की ओर बढ़ रहा है। यदि स्पष्ट राष्ट्रीय अंतरिक्ष क़ानून नहीं बना तो निवेश और नवाचार बाधित हो सकते हैं और भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दायित्व संकट में फँस सकता है। इसलिए, एक मज़बूत कानूनी ढाँचा भारत को जिम्मेदार और प्रतिस्पर्धी अंतरिक्ष शक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

UPSC Mains Practice Question

Ques: भारत के बढ़ते अंतरिक्ष कार्यक्रम और निजी क्षेत्र की भागीदारी को देखते हुए एक व्यापक राष्ट्रीय अंतरिक्ष क़ानून की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। **(150 Words)**

Page : 08 Editorial Analysis

India's democracy is failing the migrant citizen

In a democracy of 1.4 billion, every vote matters. But for millions of migrants from Bihar, democracy is quietly leaving them behind. A silent crisis is unfolding, where the Special Intensive Revision (SIR) of State electoral rolls, and at short notice, has led to the mass deletion of nearly 3.5 million migrants (4.4% of the total voters). These are the migrants who have been labelled as "permanently migrated" for being absent during house-to-house verification. These voters now face permanent disenfranchisement not just in their places of work but also at home.

In a State where migration is not just an economic choice but also a survival strategy, this sweeping administrative action is threatening to erase millions from India's democratic record. For decades, out-migration has sustained Bihar's economy and its households. Locked homes, especially among poor and most vulnerable migrants, are a common sight across villages. Increasingly, migrants either migrate with their families or shift their families to marital homes for their care and safety. Yet, this reality of circular and split-family migration is now being read by the state as an abandonment of electoral rights.

The 'sedentary citizen' is the issue

The deeper issue lies in India's electoral infrastructure, which is still designed around a sedentary citizen. Voter registration is tethered to proof of residence and in-person verification. But for migrant workers – many live in rented rooms, at construction sites, on foot paths or in slums – such documentation is either unavailable or denied.

This exclusion deepens in the context of regionalism and sub-nationalism, where migrants are often seen as job-stealers or political threats. Growing demands for job quotas in private sectors and strict domicile-based norms for government jobs reflect the larger political sentiments, which curtails the political inclusion of migrants. In host States, migrants are treated as outsiders and fears of altered electoral outcomes fuel resistance to their enfranchisement. It discourages voter registration at destinations. As a result, migrants remain stuck: unable to register in destination States, and now removed from their origin rolls.

S. Irudaya Rajan

is Chair, International Institute of Migration and Development, Kerala

Arif Nizam

is an independent migration researcher based in Bihar

A migrant's dual belonging, which is economic participation in a host State and political identity in his home State, is being demonised by the state

The findings of a study

A Tata Institute of Social Sciences, Mumbai study in November 2015, funded by the Election Commission of India, titled 'Inclusive Elections in India: A Study on Domestic Migration and Issues in Electoral Participation', confirmed the marginalisation of migrants in a host State's electoral processes. The study identifies a triple burden – administrative barriers, digital illiteracy, and social exclusion – preventing a migrant from effectively participating in electoral processes. Crucially, the study found that lower voter turnout was directly correlated with the higher migration rates in the source States. And yet, rather than bridging this turnout gap, Bihar's SIR initiative is widening the democratic deficit.

This is not just a bureaucratic failure. It is a democratic rupture. The average turnout rate in Bihar's last four Assembly elections was only 53.2%, the lowest among major Indian States. In contrast, Gujarat and Karnataka – States with fewer outbound migrants – reported an average of a turnout of 66.4% and 70.7%, respectively, in the last four elections.

Our own estimates, based on mobile visitor location register data, suggest an annual outflow of approximately seven million circular migrants from Bihar. Out of this number, 4.8 million migrate seasonally between June and September. However, half of them (2.7 million) return home during the festivals of Durga Puja, Chhath and Deepavali between October and November. This year, where there will be an Assembly election, many of the return migrants will be unable to vote as their names have been struck off. Without coordination with destination States to verify or re-enrol these voters, the deletion process becomes a de facto disenfranchisement of the poor migrants.

The limited uptake of the 'One Nation One Ration Card' Scheme in the last six years, since its launch in 2019 (nation-wide portability of ration card holders under National Food Security Act, 2013), underscores the constraints of migrants in the host States. Most migrants from Bihar avail rations in their home State, with only 3.3 lakh households availing portability in destination States as of May 2025. Dual residency, fear of losing entitlements and bureaucratic hurdles deter transfers. The same logic applies to voter IDs – they keep origin-based documents not because they are indifferent to civic duties, but because they lack security and acceptance in host States.

This dual belonging – economic participation in host States, political identity in home States – is now being demonised by the state. Migrants are being told bluntly that 'if you're not home when we knock, your right to vote vanishes'.

Along the 1,751 kilometre-long open India-Nepal border, the issue becomes even more complex. The region has long celebrated the "*roti-beti ka rishta*", a tradition of cross-border economic and marital ties. Many Nepali and Indian women migrate post-marriage, yet new documentation norms and restrictive citizenship interpretations now threaten their legal and electoral status. Here, disenfranchisement is not just regional or class-based but also gendered and xenophobic.

Time for a portable identity system

The way forward is clear. India must move toward portable, flexible, and mobile voter identity systems. The Election Commission of India must halt blanket deletions of migrants and adopt a cross-verification model with destination State voter rolls. Civil society and local governance bodies such as panchayats should be empowered to conduct migrant outreach and re-registration drives.

It is high time that the Kerala model of migration surveys should be replicated among high internal migration origin States such as Bihar and Uttar Pradesh. If these steps are not taken, India risks scripting the largest silent voter purge in post-Independence India – a purge not of enemies, but of the hard-working poor who leave home only in search of bread, dignity and work.

GS. Paper 03 **Indian Economy**

UPSC Mains Practice Question: **आंतरिक प्रवासन भारत की अर्थव्यवस्था और समाज की एक परिभाषित विशेषता है, फिर भी प्रवासी संरचनात्मक एवं प्रशासनिक बाधाओं के कारण राजनीतिक रूप से बहिष्कृत बने रहते हैं। भारत में प्रवासियों के चुनावी समावेशन को सुनिश्चित करने की चुनौतियों की समालोचनात्मक परीक्षा कीजिए। भारत के लोकतंत्र को वास्तव में प्रवासी-समावेशी बनाने हेतु सुधार सुझाइए। (150 words)**

Context :

आंतरिक प्रवासन भारत की अर्थव्यवस्था और समाज की एक परिभाषित विशेषता है, जहाँ लाखों लोग जीविका और रोज़गार के लिए मौसमी या स्थायी रूप से स्थानांतरित होते हैं। फिर भी, उनके राजनीतिक अधिकार अस्थिर बने रहते हैं। हाल ही में बिहार की मतदाता सूची से विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान लगभग 35 लाख नामों की विलोपन ने प्रवासी नागरिकों के व्यवस्थित मताधिकार से वंचन को उजागर किया है। यह केवल प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि एक लोकतांत्रिक दरार है, जो भारत के चुनावी लोकतंत्र की समावेशिता को कमजोर करती है।

मुख्य मुद्दे

चुनावी अवसंरचना में स्थायी निवासी पक्षपात

- मतदाता पंजीकरण निवास प्रमाण और व्यक्तिगत सत्यापन से जुड़ा है, जिससे किराए के कमरों, झुग्गियों या निर्माण स्थलों पर रहने वाले प्रवासी वंचित हो जाते हैं।
- चुनावी प्रक्रियाएँ स्थायी निवास मानती हैं, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रचलित चक्रीय और विभाजित परिवार प्रवासन पैटर्न को नज़रअंदाज़ करती हैं।

प्रवासियों का संरचनात्मक बहिष्कार

- प्रवासी प्रायः गंतव्य राज्यों में शत्रुता का सामना करते हैं, जहाँ उन्हें रोजगार प्रतिस्पर्धी या राजनीतिक खतरे के रूप में देखा जाता है।
- यह उन्हें गंतव्य राज्यों में पंजीकरण से हतोत्साहित करता है, जबकि मूल राज्यों में नाम विलोपित होने से वे कहीं भी मताधिकार से वंचित रह जाते हैं।

त्रिस्तरीय बोझ (टीआईएसएस अध्ययन, 2015)

1. प्रशासनिक बाधाएँ (दस्तावेज़, सत्यापन)।
2. डिजिटल निरक्षरता (ऑनलाइन प्रणालियाँ अधिकांश प्रवासियों के लिए अप्राप्य)।
3. सामाजिक बहिष्कार (बाहरी समझा जाना, राजनीतिक हाशियाकरण)।

- उच्च प्रवासन वाले राज्यों जैसे बिहार में मतदान प्रतिशत कम (53.2%) है, जबकि कम प्रवासन वाले राज्यों जैसे कर्नाटक में अधिक (70.7%)।

बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचन

- बिहार हर साल 70 लाख चक्रीय प्रवासियों का बहिर्गमन देखता है, जिनमें से आधे मौसमी रूप से घर लौटते हैं।
- गंतव्य राज्यों से समन्वय के बिना सामूहिक नाम विलोपन का मतलब है कि कई लौटने वाले मताधिकार से वंचित हो जाते हैं।

कल्याणकारी योजनाओं से तुलना

- "वन नेशन वन राशन कार्ड" (ONORC) की सीमित सफलता दिखाती है कि पोर्टेबिलिटी नौकरशाही जड़ता, अधिकार खोने के डर और दोहरी पहचान की समस्या से जूझती है।
- इसी तरह की बाधाएँ पोर्टेबल वोटर आईडी को प्रभावित करती हैं, जिससे प्रवासी राजनीतिक रूप से अदृश्य हो जाते हैं।

सीमापार और लैंगिक आयाम

- भारत-नेपाल सीमा पर पारंपरिक "रोटी-बेटी" संबंध महिलाओं के लिए मतदाता पंजीकरण को जटिल बनाते हैं।
- नए दस्तावेज़ मानदंड लैंगिक मताधिकार-वंचन को और बढ़ाने का जोखिम रखते हैं।

आगे का रास्ता

- पोर्टेबल वोटर आईडी प्रणाली: प्रवासियों को गंतव्य राज्यों से सहजता से मतदान की अनुमति दें, गृह राज्य की सूची से क्रॉस-सत्यापन द्वारा।
- डिजिटल एकीकरण: आधार, राशन कार्ड और मतदाता सूची को जोड़ें, साथ ही निजता की रक्षा करें।
- केरल मॉडल प्रवासन सर्वेक्षण: उच्च बहिर्गमन वाले राज्यों में प्रवासी मतदाताओं की पहचान और पुनः पंजीकरण के लिए अपनाएँ।
- नागरिक समाज की भागीदारी: पंचायत और एनजीओ प्रवासी पुनः पंजीकरण अभियान को बढ़ावा दें।
- नीति संवेदनशीलता: चुनावी प्राधिकरणों को प्रवासन को सामाजिक-आर्थिक वास्तविकता के रूप में देखना चाहिए, न कि नागरिक अधिकारों की अयोग्यता के रूप में।

निष्कर्ष

भारत अपने स्वतंत्रता-उत्तर इतिहास में सबसे बड़े मौन मतदाता शुद्धिकरण का जोखिम उठा रहा है — दुश्मनों का नहीं, बल्कि उन गरीब प्रवासियों का जो जीविका की तलाश में घर छोड़ते हैं। यदि लोकतंत्र को वास्तव में प्रतिनिधिक बने रहना है, तो चुनावी संस्थाओं को स्थायी नागरिक ढाँचे से विकसित होकर एक पोर्टेबल, प्रवासी-समावेशी मॉडल बनना होगा। प्रवासियों का राजनीतिक समावेशन दया नहीं बल्कि संवैधानिक गारंटी है — अनुच्छेद 14, 19 और 326 के तहत समानता का अधिकार, गतिशीलता का अधिकार और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार।